भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 221

(जिसका उत्तर सोमवार, 04 दिसंबर, 2023/ 13 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया जाना है)

पांच ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था

221. श्री रघु राम कृष्णराजू:
श्री मन्ने श्रनिवास रेड्डी :
श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पांच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य निर्धारित किया है;
(ख) यदि हां, तो क्या उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने में विनियम दर एक अनदेखा कारक है;
(ग) यदि हां, तो इस संबंध में वर्ष 1947 से अब तक निर्धारित/ प्राप्त लक्ष्यों को दर्शाते हुए तत्संबंधी तुलनात्मक ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;
(घ) इस संबंध में अब तक क्या तंत्र विकसित किया गया है और अब तक लक्ष्यों तक पहुंचने में योगदान देने वाले विभिन्न क्षेत्रों का उत्पादन कितना है; और
(ङ) 1947 से अब तक ऐसे क्षेत्रों को कितनी सहायता दी गई/परिणाम प्राप्त हुए हैं?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क)-(ख): सरकार ने वर्ष 2047 तक उन्नत अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस प्रक्रिया में यह अमृत काल की शुरुआत में 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। व्यापक आर्थिक स्थिरता के परिणामस्वरूप मजबूत रूपए की सहायता से इस सोपान को पार किया जाएगा। विनिमय दर एक उपेक्षित कारक नहीं है क्योंकि यह दुनिया में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के आकार का आंकलन करता है। आईएमएफ का अनुमान है कि भारत 2027-28 में तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी के साथ 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

(ग): भारत एक बाजार अर्थव्यवस्था है और सरकार बाजार-निर्धारित सकल घरेलू उत्पाद और विनिमय दर के माध्यम से आर्थिक प्रगति की निगरानी करती है। पिछले आंकड़े अनुलग्नक में तालिका 1 में दिखाए गए हैं।

(घ): घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजार वे तंत्र हैं जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद, विनिमय दर और सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान को निर्धारित करते हैं। वर्ष 2022-23 में अर्थव्यवस्था में व्यापक क्षेत्रों के योगदान को अनुलग्नक तालिका-2 दर्शाती है।

(ङ): सरकार वार्षिक बजटों में घोषित उपायों सहित नीतिगत प्रयास के माध्यम से आर्थिक प्रगति में भी योगदान देती है। जीडीपी को प्रत्यक्ष तौर पर बढ़ाने के लिए पिछले 9 वर्षों में सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहलों में अन्य बातों के अलावा, दिवाला और दिवालियापन (आईबीसी) संहिता का कार्यान्वयन, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण, वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) शुरू करना, कॉर्पोरेट कर में कमी, प्रभावी पूंजीगत व्यय में वृद्धि, 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की शुरुआत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश व्यवस्था का निरंतर उदारीकरण और डिजिटल अवसंरचना का निर्माण शामिल है।

अनुबंध

तालिका 1: अमरीकी डॉलर में जीडीपी और औसत विनिमय दर

वर्ष	जीडीपी (अमरीकी बिलियन डॉलर में)	विनिमय दर (₹/अमरीकी डॉलर)
1980-81	189.4	8.1
1990-91	326.6	12.8
2000-01	476.6	35.5
2010-11	1708.5	45.6
2020-21	2671.6	63.6
2022-23	3732.2	77.5

स्रोत: एनएसओ, एमओएसपीआई और आरबीआई

तालिका 2: 2022-23 में सांकेतिक जीडीपी में कृषि, उद्योग और सेवाओं का योगदान (प्रतिशत में)

कृषि	उद्योग	सेवाएँ
18.4	28.3	53.3

स्रोत: एनएसओ, एमओएसपीआई

*****